

कृषि संज्ञा

२२ सितंबर २०२५



ASCI
Agriculture Skill Council of India

CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



www.ceasi.in



प्रिय पाठकों,
हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से आप तक पहुँच पाना हमारे लिए एक विशेषाधिकार है। यह समाचार पत्र CEASI की गतिविधियों की धड़कन को दर्शाता है, जो ASCI के संरक्षण में कार्यरत है, और हमारे सामूहिक सफ़र को कौशल विकास एवं सतत कृषि की दिशा में प्रतिबिंबित करता है। यहाँ साझा की जाने वाली हर कहानी हमारी टीमों, साझेदारों और कृषि समुदायों की समर्पित भावना का प्रमाण है। हमारा मिशन स्पष्ट है: किसानों और कृषि-पेशेवरों को वह कौशल, ज्ञान और तकनीक प्रदान करना जिसकी उन्हें बदलते समय में सफल होने के लिए आवश्यकता है। नवाचार और जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मिलाकर, हम एक अधिक उत्पादक, लचीले और समावेशी कृषि क्षेत्र की नींव रख रहे हैं।
मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप इस समाचार पत्र को पढ़ें, सीखें और इसमें प्रस्तुत अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लें। आपकी सहभागिता ही विचारों को प्रभाव में बदलती है।

डॉ. सतेंद्र सिंह आर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी



प्रिय पाठकों,
CEASI का साप्ताहिक समाचार पत्र केवल गतिविधियों का सारांश नहीं है। बल्कि यह एक ऐसा मंच है, जहाँ विचारों का आदान-प्रदान, उपलब्धियों का उत्सव और भारतीय कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों जैसे डेयरी, बागवानी, कृषि मशीनीकरण, जलवायु लचीलापन आदि के भविष्य के लिए हमारी साझा दृष्टि को और मजबूत किया जाता है। प्रत्येक अंक कृषि क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नवाचार, सहयोग और प्रगति की कहानियाँ लेकर आता है।

आगे बढ़ते हुए, हमारा ध्यान ज्ञान साझा करने, नवीनतम विकासों को सामने लाने, क्षमता निर्माण करने और सफलता की कहानियाँ हर स्तर पर किसान के खेत से लेकर नीति-निर्माताओं तक पहुँचाने पर रहेगा। ताकि आधुनिक उपकरण, तकनीकें और सर्वोत्तम प्रथाएँ उन तक पहुँच सकें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि यह समाचार पत्र अभी अपने प्रारंभिक चरण में है। मैं पाठकों और हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे इसमें प्रस्तुत पहलों, प्रशिक्षणों और अद्यतनों से जुड़े रहें, और ऐसी प्रमुख उपलब्धियों व घटनाओं को साझा करें जिन्हें यहाँ प्रकाशित किया जा सके। इसके दायरे, प्रकाशन की आवृत्ति, नए अनुभाग जोड़ने और सुधार के लिए आपके विचार इसे एक आदर्श पत्रिका बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, जो हमें साथ मिलकर और अधिक मजबूत बनने के अवसर प्रदान करेगी।

जसवंत सिंह कालसी मुख्य परिचालन अधिकारी

हम कौन हैं:

“सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एग्रीकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEASI)” एक स्वायत्त संस्था है, जो “एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया (ASCI)” के अधीन कार्य कर रही है। यह संस्था कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत किसानों, मजदूरी श्रमिकों, स्वरोजगार में लगे पेशेवरों, विस्तार कार्यकर्ताओं आदि के लिए कौशल विकास और क्षमता निर्माण का कार्य करती है।

CEASI कृषि के विभिन्न उप-क्षेत्रों में स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों की शीर्ष संस्था है, जैसे कि:

- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्टिकल्चर स्किल्स इन इंडिया (CEHSI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट रेज़िलिएंट एग्रीकल्चर (CoE-CRA)
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर (CoE-AI)

हम क्या करते हैं:

- **कौशल विकास और क्षमता निर्माण:** कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में हितधारकों की आवश्यकताओं के आधार पर क्षमता निर्माण।
- **ज्ञान प्रबंधन:** वर्कफोर्स मानकों को समर्थन देने हेतु QPs, NOS, स्किल गैप रिपोर्ट और न्यूज़लेटर्स का विकास।
- **अनुसंधान:** उद्योग की मांगों के अनुसार आवश्यकताओं की पहचान और कौशल अंतर को पाटने के लिए अनुसंधान।
- **नीति समर्थन और परामर्श सेवाएं:** नवाचार साझा करने और क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने हेतु नेटवर्क का निर्माण।

हमारा विज़न

एक स्वायत्त उत्कृष्टता संस्थान जो कृषि में उच्च कौशल युक्त कार्यबल विकसित करने के लिए समर्पित है, नवाचार, तकनीकी प्रगति और सतत प्रथाओं के माध्यम से भारतीय कृषि की समृद्धि और लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्यरत है।

हमारा मिशन

राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उन्नत कृषि पद्धतियों में कौशल विकास के लिए अग्रणी संगठन के रूप में उभरना, जो सततता, लाभप्रदता, क्षमता निर्माण, ज्ञान प्रसार, नीति समर्थन और नवाचार आधारित अनुसंधान के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को प्रोत्साहित करता है।

CEASI का प्रभाव:

CEASI भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव ला रहा है, जो व्यक्तियों को सशक्त बनाने, कौशल को निखारने और देशभर में समुदायों को उन्नत करने का कार्य कर रहा है।

- ▶ 15+ राज्य
- ▶ 15 एफपीओ को प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया गया
- ▶ 20,000 कृषि / डेयरी पेशेवरों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया
- ▶ 5000+ उद्यमियों को प्रशिक्षित किया गया
- ▶ 3000+ महिलाओं को सशक्त बनाया गया
- ▶ 30,000+ जीवन को प्रभावित किया गया

कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटा, किसानों तक लाभ पहुँचाने की अपील



नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमुख कृषि मशीनीकरण संघों के साथ बैठक की। बैठक में ट्रैक्टर एंड मैकेनाइजेशन एसोसिएशन (TMA), एग्रीकल्चरल मशीनरी मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (AMMA), ऑल इंडिया कंबाइन मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (AICMA) और पावर टिलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (PTAI) के प्रतिनिधि शामिल हुए।

मंत्री ने घोषणा की कि ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरणों पर जीएसटी की दर 12% और 18% से घटाकर 5% कर दी गई है, जो 22 सितंबर से लागू होगी। इससे किसानों के लिए मशीनें खरीदना सस्ता होगा। उदाहरण के तौर पर, 35 हॉर्स पावर का

ट्रैक्टर लगभग ₹41,000 सस्ता होगा, जबकि 50 और 75 एचपी ट्रैक्टर तथा पावर टिलर, सीडर और कंबाइन हार्वेस्टर जैसे उपकरण भी कम कीमत पर उपलब्ध होंगे।

चौहान ने निर्माताओं और कस्टम हायरिंग सेंटर्स से आग्रह किया कि इस कटौती का सीधा लाभ किसानों को मिले। उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया और पारदर्शी तरीके से इसे लागू करने का आश्वासन दिया।

ओडिशा में कृषि मशीनीकरण मेलों का आयोजन



ओडिशा सरकार नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच राज्यभर में 58 कृषि मशीनीकरण मेले आयोजित करेगी। इन मेलों का उद्देश्य किसानों को मशीनरी निर्माताओं, डीलरों और वित्तीय संस्थानों से जोड़ना है ताकि आधुनिक खेती को बढ़ावा मिल सके।

इस कार्यक्रम में 4 क्षेत्रीय मेले (सोनपुर, मयूरभंज, गजपति और नबरंगपुर), 26 जिला स्तरीय मेले और 28 उप-मंडलीय मेले शामिल होंगे। हाल ही में आयोजित फार्म मशीनरी मैनुफैक्चरर्स मीट में प्रमुख सचिव डॉ. अरविंद कुमार पड्ही ने बताया कि राज्य में 2024-25 में प्रति हेक्टेयर कृषि ऊर्जा उपलब्धता 2.61 किलोवाट हो चुकी है, जिसे 2036 तक 3.50

किलोवाट और 2047 तक 4.50 किलोवाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने ₹540 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान किया है, जिससे ₹1,200 करोड़ की मशीनरी वितरित की जाएगी। सामान्य किसानों को 40% और एससी/एसटी, महिला व लघु/सीमांत किसानों को 50% सब्सिडी मिलेगी। महिला स्व-सहायता समूहों को 75% और एफआरए पट्टा धारकों को 90% सब्सिडी दी जाएगी।

डिजिटल व्यवस्था जैसे गो-सुगम पोर्टल, डीबीटी भुगतान, ई-रूपी वाउचर और ट्रेसबिलिटी कोड से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

पंजाब में पराली प्रबंधन हेतु 15,600 से अधिक मशीनें स्वीकृत



पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या को कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 15,613 फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनें किसानों को देने की मंजूरी दी है। यह पहल मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में ₹500 करोड़ की योजना का हिस्सा है।

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़ियन ने बताया कि किसानों की ओर से कुल 42,476 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सुपर सीडर मशीन सबसे अधिक पसंद की गई। अन्य लोकप्रिय मशीनों में आरएमबी प्लाऊ, मल्वर, जीरो टिल ड्रिल और रैक शामिल हैं। स्वीकृत मशीनों में से लगभग 9,000 किसानों तक पहुँच भी चुकी है।

सरकार किसानों को इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और प्रदूषण घटेगा। प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने बताया कि पिछले वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 70% की कमी दर्ज हुई और केवल 10,909 मामले सामने आए।

इसी के साथ, सरकार ने मिशन चरदीकला भी शुरू किया है ताकि हाल की बाढ़ से प्रभावित परिवारों का पुनर्वास किया जा सके। अनुमान है कि बाढ़ से लगभग ₹13,800 करोड़ का नुकसान हुआ।

नयागढ़ में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का सफल प्रदर्शन



ओडिशा के नयागढ़ जिले के सज्जनपाड़ा क्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) द्वारा ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का बड़ा प्रदर्शन किया गया। यह कार्यक्रम राज्य कृषि विभाग के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ और इसमें लगभग छह हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया।

विशेषज्ञों ने बताया कि ड्रोन तकनीक पारंपरिक छिड़काव की तुलना में कई लाभ देती है। इससे कीटनाशक समान रूप से फैलते हैं, रसायनों की बर्बादी कम होती है और श्रम लागत भी घटती है। साथ ही, किसानों व मजदूरों का हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने का खतरा भी काफी कम हो जाता है।

यह तकनीक खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए

उपयोगी मानी जा रही है, जिन्हें अक्सर श्रमिकों की कमी और बढ़ते उत्पादन खर्च जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर कृषि विभाग ने किसानों और खेतिहर मजदूरों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। आने वाले समय में इस तकनीक को अन्य जिलों में भी लागू करने का लक्ष्य है, ताकि खेती को और सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी बनाया जा सके।

भारत का लक्ष्य: 2047 तक बागवानी में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 5% से कम करना



नई दिल्ली: सरकार ने 2047 तक बागवानी क्षेत्र में कटाई के बाद होने वाले नुकसान को 15% से घटाकर 5% से कम करने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में भारत, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बागवानी उत्पादक है, कुल 365 मिलियन टन उत्पादन में से लगभग 15 मिलियन टन उपज प्रतिवर्ष खो देता है। इस नुकसान का सीधा असर किसानों की आय, पोषण सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसके समाधान हेतु व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इंजीनियरिंग दिशानिर्देश संशोधित किए जा रहे हैं तथा कोल्ड चेन अवसंरचना का डिजिटलीकरण किया जा रहा है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करना अनिवार्य माना गया है। वर्तमान में देश के पास 32-35 मिलियन टन कोल्ड स्टोरेज क्षमता है, लेकिन पैकहाउस, रिपनिंग चैंबर और शीतित परिवहन साधनों में निवेश की कमी है। वैश्विक रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट और वाणिज्यिक प्रशीतन बाजारों के तेजी से बढ़ने की संभावना को देखते हुए, भारत के कोल्ड चेन क्षेत्र में अपार अवसर मौजूद हैं, जो किसानों की समृद्धि और निर्यात क्षमता को बढ़ावा देंगे।

तिरुक्कडैयूर में एनएडीपी के तहत सब्जी खेती को बढ़ावा



मयिलाडुथुरै: उद्यान विभाग तिरुक्कडैयूर पंचायत, थरंगमबाड़ी ब्लॉक, मयिलाडुथुरै जिले में राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एनएडीपी) के तहत सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित कर रहा है। किसानों द्वारा लौकी, तुरई और करेला जैसी फसलें उगाई जा रही हैं। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों, फलों, फूलों, औषधीय पौधों और वृक्ष प्रजातियों सहित विविध फसलों के लिए अनुदान, बीज, इनपुट और कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का लक्ष्य है।

इस पहल के तहत किसानों को पारंपरिक सब्जियों के बीज, जैविक और बायो-इनपुट, समेकित पोषक तत्व एवं कीट

प्रबंधन सहायता, तथा फावड़ा, ठेला और मिट्टी पैन जैसे कृषि उपकरण वितरित किए गए। बीज आपूर्ति, पोषण प्रबंधन और जैविक खेती सहित विभिन्न गतिविधियों के लिए 80,000 रुपये से अधिक के इनपुट प्रदान किए गए हैं। इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य उपज में वृद्धि, लागत में कमी और बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है, साथ ही जिले के अधिक किसानों को सब्जी खेती में विस्तार हेतु प्रेरित करना भी है।

ओडिशा ने लॉन्च किए 15 नए उद्यान फसल किस्में, भारत का पहला रोज़ एप्पल शामिल



भुवनेश्वर: ओडिशा ने अपने कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य बीज उप-समिति बैठक में 15 नई उद्यान फसल किस्में जारी की हैं। इस पहल का उद्देश्य फसलों में विविधता लाना, किसानों की आय बढ़ाना और क्षेत्र-विशिष्ट नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। जारी की गई किस्मों में आठ ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से, दो केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान से और पाँच केंद्रीय उद्यान अनुसंधान केंद्र से शामिल हैं। इनमें विशेष रूप से रोज़ एप्पल उल्लेखनीय है, जो भारत में पहली बार जारी किया गया है और फल उत्पादन में नया आयाम जोड़ने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, कलिंग बेबी आलू अपनी विशिष्ट स्वाद विशेषता के लिए तथा कलिंग ब्लैक हल्दी औषधीय गुणों के लिए प्रमुख आकर्षण हैं।

इन नई किस्मों से उत्पादन क्षमता बढ़ने, फसलों की सहनशीलता में सुधार होने और घरेलू व व्यावसायिक दोनों मांगों को पूरा करने की उम्मीद है। सब्जियों, फलों, कंदों और औषधीय पौधों को शामिल करने वाली ये किस्में ओडिशा की उद्यानिकी आधारशिला को और मजबूत करेंगी। यह पहल कृषि नवाचार में राज्य की अग्रणी भूमिका को दर्शाती है, जिससे किसानों की आजीविका बेहतर होगी और कृषि मूल्य श्रृंखला में नए अवसर उत्पन्न होंगे।

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम से भारत की उद्यानिकी और किसान सशक्तिकरण में बढ़ावा



नई दिल्ली: सरकार ने भारत के उद्यानिकी क्षेत्र को मजबूत बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए 1,765.67 करोड़ रुपये के स्वच्छ पौधा कार्यक्रम (सीपीपी) को मंजूरी दी है, जिसके तहत वायरस-मुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल को एशियाई विकास बैंक के 98 मिलियन डॉलर के ऋण से समर्थन प्राप्त है और इसका ध्यान मुख्य फल फसलों जैसे अंगूर, संतरा और अनार पर है। कार्यक्रम के तहत पूरे देश में नौ स्वच्छ पौधा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र में तीन केन्द्र शामिल हैं—पुणे (अंगूर के लिए), नागपुर (संतरा के लिए) और सोलापुर (अनार के लिए)। बड़े नर्सरी केन्द्रों को 3 करोड़ रुपये तक और मध्यम नर्सरी केन्द्रों को 1.5 करोड़ रुपये तक सहायता दी जाएगी, जिससे प्रतिवर्ष 8 करोड़

रोग-मुक्त पौधे तैयार होंगे।

सीपीपी का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, फलों की गुणवत्ता में सुधार करना और छोटे किसानों को जैविक और अजैविक खतरों से सुरक्षित रखना है। तकनीकी प्रगति और क्षमता निर्माण की निगरानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करेगी, जबकि पुणे में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला मूल पौध प्रजातियों पर अनुसंधान करेगी। सीपीपी का केंद्रीय वेबसाइट पोषण, अपडेट और संसाधन उपलब्ध कराएगा, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स पाईपलाइन विकसित की गई है, जिससे नर्सरी पौधों का वायरस परीक्षण तेजी से और सुरक्षित तरीके से किया जा सके, और भारत में स्थायी उद्यानिकी को मजबूती मिले।

एनडीडीबी प्रबंधन में मणिपुर डेयरी का रीब्रांडिंग, उत्पाद और डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार



पूर्वोत्तर भारत में डेयरी क्षेत्र को नई गति मिली है क्योंकि मणिपुर मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड अब मणिपुर डेयरी के नाम से पुनः प्रस्तुत की गई है और इसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (NDDB) के प्रबंधन में लाया गया है। इस पहल का उद्देश्य सहकारी डेयरी को मजबूत करना और देश की डेयरी अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका का विस्तार करना है।

रीब्रांडिंग के तहत नए दूध और मूल्यवर्धित उत्पाद पेश किए गए हैं, जिनमें फोर्टिफाइड और प्रोबायोटिक उत्पाद शामिल हैं। एनडीडीबी ने ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन सिस्टम (AMCS) और डेयरी ERP प्लेटफॉर्म भी लागू किया है, ताकि पारदर्शिता, ट्रेसिबिलिटी और किसान भुगतान में सुधार हो। इसके अलावा एक बल्क मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित किया

गया है और ग्रामीण मणिपुर में महिला डेयरी सहकारी समितियों की योजना बनाई गई है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़े। 2.6 लाख पशुधन और अनुकूल परिस्थितियों के साथ, मणिपुर डेयरी हब के रूप में उभर रहा है। एनडीडीबी ने अनुदान, ऋण और क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान किया है, साथ ही Milk & More आउटलेट्स के माध्यम से रिटेल विस्तार की भी योजना बनाई गई है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में JKDFA ने डेयरी किसानों की चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित किया



शुक्रवार को जम्मू और कश्मीर डेयरी फ़ार्मर्स एसोसिएशन (JKDFA) की एक प्रतिनिधिमंडल ने बड़याल ब्रह्मना, आर.एस. पुरा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में जीत राम चौधरी (संस्थापक अध्यक्ष), सुनील शर्मा (अध्यक्ष), देविंदर सिंह (सचिव), कुलभूषण खजूरिया (अध्यक्ष, FWC एवं सदस्य, J&K किसान सलाहकार बोर्ड) और दिलिप सिंह (उपाध्यक्ष) शामिल थे। उन्होंने क्षेत्र के डेयरी सेक्टर पर हाल की बाढ़ और भारी बारिश के प्रभावों की विस्तृत जानकारी दी।

JKDFA प्रतिनिधियों ने किसानों को पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों को उजागर किया, जैसे कि पशुधन हानि, गंभीर चारा

संकट और कृषि बुनियादी ढांचे को हुए व्यापक नुकसान। क्षेत्रीय स्तर पर चर्चा के दौरान, प्रतिनिधिमंडल ने तुरंत राहत उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें आपातकालीन चारा आपूर्ति, पशुधन हानि का मुआवजा और व्यापक पुनर्वास सहायता शामिल हैं।

इस बैठक ने बाढ़ प्रभावित डेयरी किसानों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने और जम्मू और कश्मीर में इस सेक्टर की स्थायी

हिमाचल प्रदेश में पशु मित्र नियुक्ति के लिए 1,000 पद सृजित



हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को पशु मित्र नीति-2025 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में स्थानीय भागीदारी बढ़ाना और पशु चिकित्सा स्वास्थ्य तथा नस्ल सुधार सेवाओं को बेहतर बनाना है। इस योजना के तहत 1,000 स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मित्र के रूप में नियुक्त किया जाएगा, जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों और किसानों के बीच सेतु का काम करेंगे, जहाँ पशु चिकित्सा सेवाएँ गांवों से दूर हैं।

पशु मित्र गैर-स्थानांतरणीय आधार पर पशु चिकित्सा संस्थानों में कार्य करेंगे, पशुधन प्रबंधन में सहायता देंगे और मानव-पशु संघर्ष, आवारा पशु एवं अन्य स्थानीय मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाएंगे। उन्हें प्रति माह ₹5,000 का मानदेय

मिलेगा, जिसमें कार्य दिवस केवल 4 घंटे का होगा।

पात्रता के लिए उम्मीदवार का संबंधित ग्राम पंचायत या नगरीय स्थानीय निकाय का निवासी होना आवश्यक है। जिम्मेदारियों में गाय, भैंस, घोड़े और खच्चर जैसे बड़े जानवरों का प्रबंधन और विभिन्न क्षमता वाले लिफ्टिड नाइट्रोजन कंटेनरों को संभालना शामिल है। नीति का लक्ष्य पशु स्वास्थ्य में सुधार, समुदाय की भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

राष्ट्रीय संगोष्ठी में भारतीय डेयरी उद्योग की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया



NDRI ग्रेजुएट्स एलुमनी एसोसिएशन (NGAA) ने ICAR-नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (NDRI) के सहयोग से शनिवार को डॉ. डी. सुन्दरासन ऑडिटोरियम, NDRI में "भारतीय डेयरी उद्योग का वैश्वीकरण" विषय पर 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। इस आयोजन में डेयरी उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया।

पद्म भूषण डॉ. आर.एस. परोड़ा, ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज (TAAS), नई दिल्ली के अध्यक्ष, मुख्य अतिथि थे। मुख्य वक्ताओं में डॉ. एच.एस. ओबेरॉय, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप

मैनेजमेंट, और डॉ. सी. आनंदरामकृष्णन, CSIR-नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम शामिल थे। अपने स्वागत संबोधन में डॉ. धीर सिंह, निदेशक और कुलपति, ICAR-NDRI ने संस्थान की डेयरी क्षेत्र में अग्रणी योगदानों को रेखांकित किया।

इस संगोष्ठी में 400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 'मिल्कथॉन 2025', छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर का शोध एवं व्यवसायिक विचार प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। टीम NDRI ने प्रथम पुरस्कार जीता, जबकि CDFST रायपुर ने सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। डॉ. ए.के. अग्रवाल को जीवनकाल उपलब्धि पुरस्कार और डॉ. पी.एन. राजू को NGAA द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अरुणाचल प्रदेश में राज्य-विशेष कृषि नीतियों और युवा प्रशिक्षण को बढ़ावा



इटानगर/नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश ने हिमालयी और पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष भौगोलिक और कृषि-जलवायु चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य-विशेष नीति हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रस्तावों में मिट्टी और जल संरक्षण के लिए भूमि तर्जनी (लैंड टैरेसिंग) पहल का समर्थन, फसलों के क्षेत्र का विस्तार, और पूरे देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) के मॉडल पर कृषि विज्ञान स्कूलों की स्थापना शामिल है, ताकि शिक्षित युवाओं को पेशेवर कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षित किया जा सके। इन उपायों का उद्देश्य कृषि समुदाय को पुनर्जीवित करना और युवा पीढ़ियों को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करना है।

राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में 2025-26 के लिए 362.5 मिलियन टन उत्पादन लक्ष्य तय करने और बीज तथा कृषि इनपुट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की रणनीतियाँ भी प्रस्तुत की गईं। 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तहत 2,000 से अधिक वैज्ञानिक और अधिकारी 'लेब टू लैंड' पहल के माध्यम से किसानों को समय पर मार्गदर्शन देंगे। फसलों में दलहनी और तिलहन उत्पादकता बढ़ाने, धान और गेहूं की स्थिर पैदावार बनाए रखने और नकली कृषि इनपुट पर नियंत्रण के उपायों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे भारत में सतत और लचीली कृषि को मजबूत किया जा सके।

राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन – रबी अभियान 2025 सम्पन्न



नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन – रबी अभियान 2025 का सफल समापन हुआ। दो दिन चले इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इसमें विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए और रबी मौसम में उत्पादन बढ़ाने की रणनीतियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

अपने समापन संबोधन में मंत्री ने स्पष्ट कहा कि घटिया या नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाए जा रहे हैं और राज्यों से इसमें सहयोग मांगा।

मंत्री ने किसान कॉल सेंटर्स को और प्रभावी बनाने तथा किसानों की शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दायरा और बढ़ाने का भी आह्वान किया।

चौहान ने कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य स्तरीय कृषि विस्तार तंत्र को सशक्त बनाने पर बल दिया और आगामी विकसित कृषि संकल्प अभियान (3 अक्टूबर से) में राज्यों की सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

प्रधानमंत्री मोदी 23 अगस्त को ₹2,481 करोड़ की राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की शुरुआत करेंगे



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) की शुरुआत करेंगे। यह केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम ₹2,481 करोड़ का है, जिसका उद्देश्य 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना और 1 करोड़ किसानों को लाभ पहुँचाना है।

नीति आयोग द्वारा परिकल्पित और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू इस मिशन के लिए केंद्र (₹1,584 करोड़) और राज्य सरकारें (₹897 करोड़) संयुक्त रूप से धन उपलब्ध कराएंगी। इस योजना के लिए किसानों का पंजीकरण पहले से जारी है।

दो वर्ष का यह कार्यक्रम उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि करने, लागत घटाने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ-साथ ग्रामीण रोजगार सृजन पर केंद्रित है।

इसका कार्यान्वयन ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टरों में होगा, जिसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।

योजना में 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर, सरल प्रमाणन, एकीकृत ब्रांडिंग और रियल-टाइम जियो-टैग्ड मॉनिटरिंग जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं ताकि पारदर्शिता बनी रहे और प्राकृतिक उत्पादों को बढ़ावा मिल सके।

स्वतंत्रता दिवस: केंद्रीय मंत्री ने किसानों के हितों की पुनः पुष्टि की, रबी फसल मार्गदर्शन के लिए वैज्ञानिक करेंगे गाँवों का दौरा



नई दिल्ली, 15 अगस्त: स्वतंत्रता दिवस समारोह में पूसा कैंपस पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किसानों को केंद्रीय कृषि मंत्री ने आश्वासित किया कि उनके हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने घोषणा की कि 3 से 18 अक्टूबर तक कृषि वैज्ञानिक गाँवों का दौरा करेंगे और रबी फसल में सुधार हेतु मार्गदर्शन देंगे।

मंत्री ने किसानों से स्वदेशी आंदोलन अपनाने और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि ऐसे विकल्प अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को सभी नीतिगत निर्णयों में संरक्षण

मिलेगा, जिसमें व्यापार समझौते भी शामिल हैं।

कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने सरकारी जवाबदेही पर बल दिया और कहा कि जिन कंपनियों के कीटनाशकों से फसलें प्रभावित हुईं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने दोहराया कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में हैं और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए निरंतर समर्थन दिया जाएगा।

कार्यक्रम में राज्य मंत्री, कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और आईसीएआर के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

असम में डेयरी और स्ट्रीट फूड हितधारकों के लिए गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (CEDSI) ने 16 सितंबर 2025 को अपने प्रशिक्षण केंद्र, c/o डायरेक्टरेट ऑफ डेयरी डेवलपमेंट, खानापारा, असम में गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा पर दूसरा बैच का जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 30 प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें पारंपरिक मिठाई बनाने वाले, डेयरी सहकारी समितियों (DCS) के सदस्य और असम के स्ट्रीट फूड विक्रेता शामिल थे। सत्र का संचालन डॉ. मनशी दास, हेड, फूड टेक्नोलॉजी विभाग, असम स्किल यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। प्रतिभागियों को स्वच्छता प्रथाओं को लागू

करने, पारंपरिक मिठाइयों और डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और स्ट्रीट फूड को सुरक्षित रूप से संभालने के तरीके सिखाए गए।

इंटरएक्टिव प्रदर्शन में उचित भंडारण, स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वाद व पोषण बनाए रखने की तकनीक पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने नियमों का पालन करते हुए ग्राहक विश्वास बढ़ाने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया। प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट हुआ कि कार्यक्रम स्थायी और सुरक्षित खाद्य प्रथाओं को बढ़ावा देने में सहायक है।

यह पहल CEDSI की असम में डेयरी और स्ट्रीट फूड क्षेत्र में कौशल विकास और क्षमता निर्माण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।



हरियाणा में EKL CSR फाउंडेशन के सहयोग से FPO नेतृत्व क्षमता सशक्त बनाने का कार्यक्रम

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया (CEFMI) ने एसकॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड (EKL) के सहयोग से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एसकॉर्ट्स कुबोटा एडवांस्ड फार्मिंग इंस्टिट्यूट (EKFAI) में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन्स (FPOs) के लिए 3-दिवसीय रेजिडेंशियल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर 2025 तक दो बैचों में आयोजित किया गया और इसमें 35 FPOs के 75 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स (BoDs) और CEOs शामिल हुए, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए। प्रशिक्षण का उद्देश्य FPOs की संगठनात्मक संरचना और शासन को मजबूत करना, कृषि यंत्रों की समझ बढ़ाना और

कृषि व्यवसाय के वित्तीय साधनों के बारे में जानकारी देना है। कार्यक्रम में नेतृत्व कौशल, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और सतत यंत्र समाधान पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे सदस्य किसानों को सीधे लाभ मिल सके।

इंटरएक्टिव सत्र, केस स्टडी और समूह चर्चाओं के माध्यम से FPO नेताओं को अनुभव साझा करने, संचालन चुनौतियों का समाधान खोजने और सामूहिक विकास के अवसरों का पता लगाने का अवसर मिला। रेजिडेंशियल प्रारूप ने गहन सीखने का माहौल बनाया, जिसमें सहकर्मी-से-सहकर्मी सीखने और सहयोग को बढ़ावा मिला।



अयोध्या में शाश्वत मिठास पहल के तहत सतत गन्ना खेती की तकनीक का प्रदर्शन

शाश्वत मिठास पहल के तहत, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फार्म मेकेनाइजेशन स्किल्स इन इंडिया(CEASI) ने UPL SAS लिमिटेड के सहयोग से अयोध्या में सतत गन्ना खेती को बढ़ावा दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों से अवगत कराना है, जो उत्पादन बढ़ाने के साथ प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशीलता बढ़ाती हैं।

अब तक, 500 किसानों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें 90 असंगठित और 3 संगठित किसान समूह शामिल हैं, ताकि मौजूदा खेती की प्रथाओं को समझा जा सके और सुधार के क्षेत्र पहचाने जा सकें। इसके आधार पर गांव स्तर पर प्रदर्शन पोट लगाए गए हैं, जहां जल उपयोग की दक्षता, मिट्टी की सेहत और जैविक उर्वरकों के उपयोग जैसे सर्वोत्तम उपाय

दिखाए जा रहे हैं।

हाल ही में, एक मॉडल पोट पर किसान फील्ड डे आयोजित किया गया, जहां किसानों ने नियंत्रण पोट के साथ तुलना की। ZEBA तकनीक का प्रदर्शन बेहतर फसल वृद्धि, मिट्टी में नमी बनाए रखने और सिंचाई की आवश्यकता कम करने में सहायक साबित हुआ। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक किसानों ने भाग लिया और सतत व जल-संवेदनशील खेती अपनाने में गहरी रुचि दिखाई। UPL, KM शुगर मिल्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (FPOs) जैसे प्रमुख हितधारकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया, जो गन्ना क्षेत्र में पर्यावरणीय स्थिरता और समावेशी विकास की साझा दृष्टि को मजबूत करता है।





CEASI

CENTRES OF EXCELLENCE FOR
AGRICULTURE SKILLS IN INDIA



(CEASI), Unit No. 101, First Floor, Greenwoods
Plaza, Block 'B' Greenwoods City, Sector-45,
Gurugram, Haryana-122009



+91 74287 06078



info@cedsi.in



www.ceasi.in



@ceasi_india